सेन्ट्रल जोन इंश्योरेंस एम्पलाईज एसोसियेशन

(ए.आई.आई.ई.ए. से संबद्ध)

33, प्रभांजलि, आर.डी.ए. कालोनी, टिकरापारा, रायपुर (छ.ग.)

अध्यक्ष : का. एन. चक्रवर्ती

महासचिव : का. डी. आर. महापात्र

परिपत्र क्र. : 02/2020

दिनांक : 11/08/2020

मध्य क्षेत्र के समस्त साथियों के नाम

सीजेडआईईए कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक 8 अगस्त को सीजेडआईईए कार्यकारिणी समिति की वर्चुअल (ऑनलाइन) बैठक अध्यक्ष काम. एन. चक्रवर्ती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सीजेडआईईए के इतिहास में पहली बार करोना महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के चलते भौतिक रूप से मिलने में हो रही समस्याओं के कारण यह ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में सभी मंडलों के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने शिरकत की। बैठक में एआईआईईए के महासचिव काम. श्रीकांत मिश्रा भी शामिल थे।

बैठक के प्रारंभ में सीजेडआईईए के विगत सम्मेलन के बाद हमारे बीच से बिछुड़ गये साथियों, आरडीआईईयू के पूर्व उपाध्यक्ष व सीटू के पूर्व छग महासचिव काम. अजीत लाल, बीडीआईईयू के पूर्व महासचिव काम. सरवर अंसारी, एआईआईईए के सक्रिय साथी काम. सुभाष चौधरी, केएमडीओ के पूर्व महासचिव काम. सरदेन्दु बागची, सीटू नेता काम. श्यामल चक्रवर्ती, किसान सभा के पूर्व महासचिव काम. के. वरदराजन, मुम्बई डीओ -3 के काम. डी.व्ही. तेली, आईईयू , इंदौर के पूर्व महासचिव काम. भागचंद मलैया तथा भोपाल मंडल के काम. नंदिता सूद, कन्हैयालाल शिवनानी, अशोक बॉथम, ग्वालियर मंडल के काम. मुकेश कुशवाहा एवं करोना महामारी तथा प्राकृतिक आपदाओं एवं सीमा पर शहीद हुए सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

यह बैठक इस मध्य 19 जुलाई को सीजेडआईईए सचिव मंडल, 2 अगस्त को एआईआईईए सचिव मंडल तथा 5 अगस्त को एआईआईईए सहित प्रथम श्रेणी व विकास अधिकारी संगठन के संयुक्त मोर्चे की सम्पन्न हुई बैठक की रोशनी में सीजेडआईईए के विगत सम्मेलन के बाद से लेकर अब तक वैश्विक, राष्ट्रीय, औद्योगिक परिस्थितियों में आये बदलावों के अनुरुप राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग की हिफाजत व वेतन पुनर्निर्धारण हासिल करने के भावी संघर्ष की जिम्मेदारियों के तहत संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा और उसके सुदृढ़िकरण के उद्देश्य से बुलाई गई थी। बैठक में एआईआईईए सचिव मंडल के निर्णय के अनुरूप विस्तृत चर्चा के बाद प्रमुख रूप से निर्णय लिये गये।

वैश्विक स्थिति :

कार्यकारिणी समिति का मत था कि विगत सम्मेलनों के बाद दुनिया में करोना महामारी के संकट ने पूंजीवादी व्यवस्था के वर्ग चरित्र और एक व्यवस्था के रूप में इस महामारी से निपटने में उसकी विफलता को पूरी तरह उजागर कर दिया है । पूंजीवाद इस संकट का सामना करने में अक्षम है यह पुनः प्रमाणित हुआ है । विगत तीन दशकों में नवउदारवाद के नाम पर सार्वजनिक सेवाओं के निजीकरण जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था भी शामिल है के चलते यह संकट और अधिक व्यापक हो गया । स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामाजिक हस्तक्षेप से राज्यों के हाथ खींचने और उसे मुनाफे के लिए निजी हाथों में सौंपने की त्रासदी मानव समाज भोग रहा है । अब तक दुनिया के 2, 08,12,367 लोग इससे प्रभावित हुए हैं जिनमें 63,53,037 सक्रिय मामले है तो 1,37,13,003 लोग स्वस्थ हो गए है, वहीं 7,45,327 लोगों ने जानें गवाई हैं । इस तबाही में पहले पायदान पर अमरीका, दूसरे में ब्राजील और भारत तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। यह कहां जाकर रुकेगा अभी कहना कठिन है । विकसित पूंजीवादी देशों में मौत आनुपातिक रूप से अधिक है । स्वास्थ्य के भारी भरकम बजट के बावजूद वहां इसे निजी बीमा व कारपोरेट की दया पर छोड़ दिया गया था। अमरीका, ब्रिटेन, ब्राजील जहां धुर दक्षिणपंथी सरकार और नवउदारवादी सरकार है, वहां भयावह विनाश हुए हैं । ये वही सरकारें है , जहां महामारी को रोकने की तैयारियों में वैज्ञानिक राय मशविरा को कोई तरजीह नहीं दी जा रही थी । दूसरी ओर समाजवादी देश इससे निपटने में कहीं अधिक सफल रहे है और उसका सबसे बड़ा कारण राज्य का सामाजिक हस्तक्षेप और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचा रहा। इसका विश्व अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव हुआ है। लगभग सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं का कहना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी । यूएनओ की विश्व आर्थिक परिस्थिति

एवं संभावना रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था में 3.2 प्रतिशत संकुचन हो सकता है , विश्व बैंक ने जी डी पी में 3.9 प्रतिशत की कमी का अनुमान लगाया है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक असमानता, बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ रही है । पूंजीवाद अपने चरित्र के अनुरूप इस संकट का बोझ अपने देशों की मेहनतकश जनता पर ही थोप रहा है और पूंजीपतियों का मुनाफा कायम रखने में लगा है।

देश की स्थिति

कार्यकारिणी समिति ने नोट किया कि हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था तो इस संकट के पहले ही संकटग्रस्त थी जिसका विश्लेषण हमने अपने सम्मेलनों में किया था अब वह और अधिक संकटग्रस्त हो गई है । इस महामारी के बाद मई अंत में घोषित पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़े देश में भयानक मंदी को दर्शा रहे है , हमारी जीडीपी 11 साल के सबसे निचले स्तर 3.1 प्रतिशत पर पहुंच गई है जबकि यही 2019-20 में 4.2 प्रतिशत थी । इसमें मार्च माह के अंतिम सप्ताह के 7 दिन ही शामिल है याने तालाबंदी के बाद की तिमाही के आंकड़े और गिरावट दर्शाएंगे । हमारे देश में भी इस संकट ने पूंजीवादी सरकारों के वर्ग चरित्र को नग्नता से रेखांकित किया है । उदारीकरण के नाम पर समूची स्वास्थ्य व्यवस्था के निजीकरण ने संकट को और गहरा किया है । भारत में सबसे पहले केरल में 30 जनवरी को यह मामला सामने आया और केरल सरकार ने उसके साथ ही अपनी तैयारी प्रारम्भ कर ली । केरल के वाम मोर्चा सरकार द्वारा इस मामले में की गई पहल को पूरी दुनिया में सराहा गया है । दूसरी ओर केंद्र सरकार गुजरात में नमस्ते ट्रंप और मध्य प्रदेश में सरकार परिवर्तन में व्यस्त थी । उसके बाद 4 घंटे के नोटिस पर बिना किसी पूर्व तैयारी के तालाबंदी के घोषणा और इस दौरान लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिए जाने का नतीजा यह हुआ कि लाखो की संख्या में रोजगार व भोजन के अभाव में प्रवासी मजदूर सड़कों पर पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़े । लगभग 200 से अधिक लोगों ने तो रास्ते में दम तोड़कर जान दे दी । इस दौरान केंद्र सरकार की उदासीनता, संवेदनहीनता और अमानवीयता नग्न रूप से उजागर हुई । अब इसे पूरी तौर पर राज्यों और आम लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है । शुरुआत में इस महामारी का भी सांप्रदायीकरण करने की घृणित कोशिश की गई। इस महामारी ने तथाकथित गुजरात माडल की कलई खोल दी । स्वास्थ्य पर सबसे न्यूनतम खर्च ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है । भारत में प्रति हजार 0.8 डाक्टर और 0.7 बिस्तर है । इस संकट से लगभग 14 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए। मांग में गिरावट से सभी क्षेत्रों में उत्पादन में भारी गिरावट है । लोगो को ऐसे संकट के समय मदद और सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की बजाय तथाकथित 20 लाख करोड़ के जिस पैकेज की घोषणा की गई वह मेहनतकश जनता की मदद के बजाय ऋण पर केन्द्रित अधिक है । उसका लाभ भी केवल बड़े पूंजीपति ही उठा रहे हैं।

ट्रेड यूनियन आंदोलन के सभी अग्रिम पंक्ति के मजदूरों को आगामी छह माह 10 हजार रूपए के अतरिक्त मदद देने, सभी गैर आयकरदाता को 7500 रूपए की आगामी छह माह मदद करने, सभी जरूरतमंद परिवार को प्रति व्यक्ति आगामी छह माह 10 किलो मुफ्त अनाज देने, मनरेगा में 200 दिन का काम देने जैसी मांगों को अनसुना कर अपने ही कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते पर रोक लगा रही है । तालाबंदी अवधि में वेतन कटौती न करने के अपने ही आदेश को मालिकों के दबाव में उसने वापस ले लिया ।

केंद्र सरकार इस आपदा को अवसर में बदलने पूरे देश की सभी सार्वजनिक सम्पत्ति को निजी देशी-विदेशी पूंजी के हवाले करने में जुटी है । यह संकट के समय इस सरकार का सबसे घिनौना चेहरा है। एक ओर करोना की आड़ में तमाम जनतांत्रिक अधिकार और विरोध के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक है दूसरी ओर वह आत्मनिर्भरता के नाम पर आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रक्षा, कोयला, इस्पात, ऊर्जा, अनुसंधान, बिजली सबका निजीकरण और प्राकृतिक संसाधनों की बोली लगा रही है। बीमा क्षेत्र में विरोध के बावजूद आई पी ओ जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है , श्रम कानूनों में बदलाव कर काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए जा रहे है । पूरे देश में करोना की आड़ में धारा 144 लगाकर तमाम विरोध के स्वर को दबाया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में तमाम कानूनों को बदलने अध्यादेश जारी कर किसानों को गुलाम बनाया जा रहा है।

सरकार के इन कदमों के खिलाफ प्रतिरोध भी इस अवधि में तीखे हो रहे है । पूरे देश में 21 अप्रैल को अग्रिम पंक्ति के रक्षा कर्मी , 22 मई व 3 जुलाई को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, 16 जून को किसान संगठनों ने 23 जुलाई को किसान व मजदूर संगठनों ने देश भर में प्रदर्शन किए । कोयला मजदूरों ने 2 से 4 जुलाई को अभूतपूर्व हड़ताल संगठित की वे 18 अगस्त को पुनः कोयला क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ एक दिन की हड़ताल कर रहे है । इसमें बी एम एस भी शामिल है । 9 अगस्त को समस्त केंद्रीय ट्रेड यूनियन व किसान संगठन देशव्यापी सत्याग्रह किए हैं । इसका अर्थ है आक्रमण सर्वव्यापी है तो उसका मुकाबला करने सर्वव्यापी आंदोलन की पहल हो रही है। करोना से अपनी हिफाजत के लिए आवश्यक सावधानियों के साथ इसका व्यापक एकजुटता के साथ मुकाबला करने सर्वव्यापी

पहल की जरूरत है ।

एलआईसी का संकट में भी बेहतरीन प्रदर्शन

कार्यकारिणी समिति ने नोट किया कि एल आई सी ने इस संकट के दौरान भी वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो प्रगति की है वह अभूतपूर्व है। यदि करोना महामारी और अर्थव्यवस्था में संकट न होता तो यह और भी बेहतर होता । एल आई सी ने 1,77,977 करोड़ रुपए की प्रथम प्रीमियम आय एकत्र की है । समूह बीमा ने एक इतिहास कायम कर एक लाख करोड़ की सीमा पार कर 1,26,696.21 करोड़ रुपए की राशि एकत्र कर 39.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है । निगम ने 12 प्रतिशत वृद्धि के साथ 3,79,062 करोड़ रुपए की कुल प्रीमियम आय एकत्र की है । निगम की कुल आय 9.83 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 6,15,882 करोड़ रुपए रही । निगम की कुल संपत्ति 31,96,214.81 करोड़ रुपए हो गई है । एआईआईईए ने इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद भी एल आई सी में आईपीओ जारी करने के लिए बोली सलाहकार नियुक्ति प्रक्रिया के निर्णय के खिलाफ वित्त मंत्री को संयुक्त मंच से पत्र लिखा है । एआईआईईए ने सभी राजनीतिक दलों को भी इसके खिलाफ संयुक्त मंच से पत्र लिखा है और उनसे इसके विरोध की अपील की है । मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सरकार डीलायट टच टोमेट्सू और एडेलवेस फाइनेंशियल सर्विसेज को इस हेतु सलाहकार नियुक्त कर रही है । एआईआईईए सचिव मंडल ने इस सवाल पर देश भर में सांसदों से मिलने व अभियान के साथ अन्य कार्यवाहियों का आव्हान किया है ।

आईपीओ व निजीकरण के खिलाफ अभियान

1. इस सवाल पर बीमा कर्मचारियों, बीमा धारकों, अभिकर्ताओं के साथ सभी स्टेक होल्डर को एकजुट करने उनके मध्य अभियान चलाया जाए, इस प्रक्रिया में बीमा धारकों को यह विश्वास भी साथ -साथ प्रदान किया जाये कि जागरुक ट्रेड यूनियन उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है अत: एल आई सी के प्रति उनका विश्वास कायम रहे ।
2. सभी किस्म के ऐसे व्यक्ति जो समाज में मत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं ऐसे एकेडमिक्स, अर्थशास्त्रियों, बुद्धिजीवियों व समाज के प्रबुद्धजनों से हमारे पक्ष में इस विषय को लेख इत्यादि माध्यमों से उठाने का आग्रह किया जाए।
3. 9 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो दिवस के दिन को 'सार्वजनिक क्षेत्र की एलआईसी व आम बीमा कंपनी हिफाजत दिवस ' के रूप में मनाया जाये । इस दिन शारीरिक दूरी व कोवीड नियमों का पालन करते हुए सभी साथी अपने घर की बालकनी में इन मांगों की तख्ती लेकर अपने परिजनों के साथ सुबह 10 से 10.30 के मध्य प्रदर्शन करें और इसकी फोटो सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों में प्रसारित करें । अन्य ट्रेड यूनियन के जो भी कार्यक्रम हो उसमे भागीदारी करें । (यह सम्पन्न हो गया है ।)
4. 18 अगस्त को कोयला मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में एकजुटता के लिए इस दिवस को निजीकरण विरोधी व सार्वजनिक क्षेत्र हिफाजत दिवस के रूप में मनाने बिल्ला व काली पट्टी धारण कर कार्य करें और भोजनावकाश में द्वार प्रदर्शन करें।
5. एआईआईईए सचिव मंडल के निर्णय अनुसार आईपीओ के सवाल पर सरकार यदि संसद में एलआईसी एक्ट में संशोधन विधेयक लाकर या अध्यादेश जारी कर अपने हिस्सेदारी घटाने कदम उठाती है तो इसके खिलाफ उसके तुरन्त बाद एक दिवसीय हड़ताल के लिए तैयार रहें ।
6. अगस्त माह में सभी सांसदों से मिलकर इस विषय पर समर्थन जुटाया जाये।

वेतन पुनर्निर्धारण

बीमा उद्योग की प्रगति के अनुरूप बेहतर वेतन पुनर्निर्धारण के मामले में 21 जुलाई को एआईआईईए सहित संयुक्त मंच की ओर से प्रबंधन को पत्र लिखा गया है। एआईआईईए सचिव मंडल ने भी परिस्थिति का आकलन कर प्रबंधन से स्पष्ट रूप से बिना किसा विलंब के सुधार प्रस्ताव के साथ इस विषय पर तत्काल चर्चा आहूत करने की मांग की है । इस सवाल पर भी एआईआईईए के निर्णय अनुसार संपूर्ण एकता के साथ हमे संघर्ष के लिए तैयार रहना है ।

कार्यकारिणी समिति ने इस अवधि में 8 जनवरी 2020 के देशव्यापी हड़ताल, बीमा में आई पी ओ संबंधी बजट में घोषणा के खिलाफ 4 फरवरी के बहिर्गमन हड़ताल और वेतन पुनरीक्षण हेतु मार्च माह में हुए आंदोलन कार्यक्रम को सफल बनाने, मध्य क्षेत्र में साथियों ने जो जबर्दस्त अभियान चलाया, उसके लिए सभी साथियों को बधाई दी। इस मध्य 19 जुलाई को संपन्न हुई सीजेडआईईए सचिव मंडल ने भी मध्य क्षेत्र में इस दौरान चले अभियान की समीक्षा की थी । सचिव मंडल ने करोना संकट के समय मजदूरों और वंचितों की सहायता के लिए मध्य क्षेत्र के विभिन्न मंडलों में चलाए गए राहत अभियान के लिए साथियों को बधाई दी । पूरे देश में एआईआईईए के आव्हान पर 5 करोड़ से अधिक राशि एकत्र कर बीमा कर्मियों ने अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान दिया है । मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश दोनों राज्य के मुखयमंत्री सहायता कोष में 5 लाख प्रत्येक की राशि दिए गए है । मध्य क्षेत्र में कुल 14,86,240 रुपए एकत्र किए गए । कार्यकारिणी समिति ने इस कार्य के लिए सभी

साथियों को बधाई देते हुए निर्णय लिया है कि 7 दिन के अंदर इस मद में एकत्रित सभी राशि सीजेडआईईए मुख्यालय भेज दिएं जाए ताकि अंतिम किश्त का भी भुगतान सम्बन्धित कोष में कर दिया जाय। कार्यकारिणी समिति ने साथ ही नोट किया कि राष्ट्रीयकृत बीमा उद्योग के हिफाजत के लिए 19 जनवरी के राष्ट्रीयकरण दिवस पर पर्चा वितरण व अन्य कार्यक्रम किए गए । वेतन पुनर्निर्धारण के सवाल पर भी संयुक्त परिपत्र इत्यादि जारी किए गए, महिला दिवस पर समूचे मध्य क्षेत्र में भी सफल कार्यक्रम किए गए । 1 मई दिवस पर ध्वजारोहण सहित विविध कार्यक्रम हुए । 1 जुलाई को एआईआईईए स्थापना दिवस के कार्यक्रम को भी संकट के इस अवधि में अनेक नए रूप में आयोजित किए गए और पहली बार डिजिटल तकनीक का उपयोग कर कामरेड चंद्रशेखर बोस, कामरेड सुधाकर ऊध्वरेषे, कामरेड वी सान्याल, कामरेड श्रीकांत मिश्रा व कामरेड एन चक्रवर्ती तथा महासचिव के संदेश साथियों तक पंहुचाने के प्रयास किए गए ।

संगठन को संगठित करो

कार्यकारिणी समिति ने इस दौरान लंबे संघर्ष के बाद उद्योग में नये भर्ती हुए सभी साथियों का अभिनन्दन किया और अब इन्हें संगठन में सक्रिय करने का आव्हान किया। संगठनात्मक स्तर पर हमारे साथियों के साथ नियमित संवाद के साथ ही हमारे संघर्षों और बातों को आम लोगों तक पहुंचने के लिए सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों का उपयोग करने पर भी जोर दिया गया। जल्द ही नियमित अंतराल में साथियों को शिक्षित करने भी इस माध्यम का उपयोग कर कार्यक्रम, ट्रेड यूनियन कक्षाएं किए जाएं । मण्डल स्तर पर भी कार्यकारिणी समिति व अन्य इकाइयों की बैठके तत्काल आयोजित की जाएं । कार्यकारिणी समिति का यह मत था कि आज के मौजूदा दौर में जब समाज में साम्प्रदायिक आधार के साथ ही हर किस्म के विभाजन की मुहिम चलाई जा रही है जिसका एकमात्र उद्देश्य मेहनतकशों की एकता को विखंडित कर देश के समस्त संसाधनों को बेरोकटोक निजी पूंजी के हवाले करने सारी बाधाओं को समाप्त कर देना है । हमें हमारे साथियों की एकता को और मजबूत करने होंगे। आज सभी संस्थाओं का सांप्रदायीकरण के साथ ही तमाम जनतांत्रिक अधिकार खत्म करने की मुहिम चलाई जा रही है । जो भी आवाज उठाए उन्हें जेल की सीखचों के पीछे भेजा जा रहा है । अपनी विफलता से ध्यान बंटाने हर हथकंडा का इस्तेमाल हो रहा है, मीडिया असल मुद्दों की बजाय रोज नए नारे उछाल कर सरकार का कवच और भोंपू वन गया है । ऐसे समय हमें हर तरह से आज की चुनौतियों का मुकाबला करने संगठन को हर स्तर पर संगठित करना होगा । हमें कामरेड एन.एम. सुंदरम् स्मृति स्टडी सर्कल प्रारंभ करना होगा। सभी सदस्यों तक संदेश तुरंत प्रेषित करने सोशल मीडिया व तकनीक का उपयोग करना होगा। जिन मंडलों का वार्षिक विवरण लंबित है, उसे तत्काल जमा करना होगा तथा 'आंदोलन की खबर' व 'इंश्योरेंस वर्कर' की सदस्यता नवीनीकरण का काम समय पर करना होगा। हमें साथ ही हमारे अभियानों में 'भारत के लिए लोग मंच' का सक्रिय रूप से उपयोग करना होगा।

कार्यकारिणी समिति की इस बैठक को संबोधित करते हुए एआईआईईए के महासचिव काम. श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि संकट की अवधि में भी भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रदर्शन अभूतपूर्व है, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके बावजूद भारत सरकार हमारे इस महान संस्थान के निजीकरण के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने एलआईसी के आईपीओ जारी करने के सरकार के फैसले के खिलाफ बीमा कर्मियों से पूरी सांगठनिक एकता के साथ एआईआईईए के निर्णय को संपूर्ण रूप से लागू करने का आव्हान किया। उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों पर विस्तार के साथ सभी पहलुओं पर अपनी बात रखते हुए आश्वस्त किया कि बीमा उद्योग की देयक क्षमता के अनुरूप बीमा कर्मियों के लंबित वेतन पुनर्निर्धारण को हासिल करने एआईआईईए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विभिन्न लंबित मुद्दों पर एआईआईईए की पहलकदमी की जानकारी भी बैठक में दी।

एआईआईईए के उपाध्यक्ष काम. बी. सान्याल ने अपने संबोधन में कहा कि एक ओर देश 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, दूसरी ओर एलआईसी में आईपीओ के जरिये हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर देशभक्ति के नाम पर अंधराष्ट्रवाद थोपने की कोशिश हो रही है, दूसरी ओर देश के आधार स्तंभ सार्वजनिक क्षेत्र की निजी देशी-विदेशी पूंजी की लूट के लिए बोली लगाई जा रही है। यह बीमा कर्मचारियों के लिए कठिन समय है, लेकिन हर हाल में हमें इसे पराजित करने आगे बढ़ना होगा।

हमें आशा है हमारे साथी इन निर्णयों के सक्रिय अमल में जुटेंगे।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ...

आपका साथी

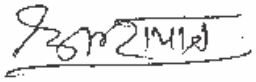

(डी.आर. महापात्र)

महासचिव